खोरी में पुनर्वास बिना विध्वंस...

पेज एक का शेष

हटाया जाता है तो प्रशासन अपना पूरा प्लान मीडिया के जरिए वहां की आबादी को बताता है। ताकि उस इलाके के लोग उस मानसिक स्थिति का सामना करने को तैयार रहें। खोरी किस तरफ से उजड़ेगा, कोई नहीं जानता। खोरी में अवैध रूप से बने मंदिरों और मस्जिदों को अभी तक चिन्हित किया गया है या नहीं, क्या उन्हें गिराने पर कोई साम्प्रदायिक हिंसा का अंदेशा तो नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारियों की सूचना सार्वजनिक नहीं है। जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी यह खबरें मीडिया में तो छपवा रहें हैं कि यहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जो अपराधी हैं लेकिन उसकी यह चाल मौके पर तब नाकाम हो जाती है जब धरने पर तिलक लगाए, घूंघट किए हुए, बिन्दी लगाए सभी समुदायों की महिलाएं और पुरुष प्रदर्शन करते नजर आते हैं। यहां तो उनकी पहचान कपड़ों तक से नहीं हो पा रही है।

साढ़े तीन लाख वोटों की कोई कीमत नहीं

खोरी-लकड़पुर में करीब साढ़े तीन लाख मतदाता रहते हैं। पिछले दो चुनावों (विधानसभा और लोकसभा) से उन्होंने बडखल से भाजपा प्रत्याशी सीमा त्रिखा और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कृष्णपाल गूजर को वोट डाले हैं। खोरी में बाकायदा भाजपा की यूनिट है और तमाम पदाधिकारी जब भीड़ जमा करनी होती है तो यहां से लोगों को ट्रकों और बसों में ले जाते हैं। इतना ही नहीं यहां दिल्ली के भाजपा नेता भी सक्रिय रहते हैं। जिसमें सांसद रमेश विधूड़ी और रामबीर सिंह विधूड़ी प्रमुख हैं। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल, एमपी, राजस्थान के रहने वाले मजदूर तबके या छोटा-मोटा काम करने वाले लोग हैं।

खोरी में पिछले बीस साल से घर बनाकर रह रहे और कारपेंटर का काम करने वाले सुरेश ने बताया कि वो भाजपा कार्यकर्ता है। उसने बाकायदा यहां पर पार्टी का प्रचार किया, मतदान से एक दिन पहले पर्चियां बांटी और चुनाव वाले दिन मतदान केंद्र पर पार्टी के लिए हाजिर रहा है। इलाके के संघ पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख आदि उसे जानते हैं लेकिन अब जब हमारे ऊपर यहां विपदा आई है, किसी का कोई अता-पता नहीं है। हम लोगों ने सीमा त्रिखा और कृष्णपाल गूजर के दफ्तरों में फोन मिलाए, मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। अभी 20-25 दिन पहले सीमा त्रिखा लकड़पुर में मास्क बांट कर गई हैं लेकिन अब जब हम उजड़ने के कगार पर हैं तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। साढ़े तीन लाख वोट कम नहीं होते हैं।

मेधा पाटकर से मांगी मदद

खोरी-लकड़पुर के लोग अब बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश को याद कर रहे हैं। कितने ही लोगों को यहां स्वामी जी व्यक्तिगत रूप से जानते थे। कोई विपदा आने पर यहां के लोग स्वामी अग्निवेश को बुला लेते थे। स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा स्थापित किया था। उसी से जुड़े कुछ एक्टिविस्ट यहां खोरी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने अब मेधा पाटकर से मदद मांगी है। मेधा पाटकर आंदोलन की नई रूपरेखा बनाएंगी या मात्र बयान के जरिए इन्हें समर्थन देंगी, अभी यह साफ नहीं है। लेकिन खोरी के लोगों का विस्थापन अब राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है।

मजदूर मोर्चा ने 7 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसके फैसले पर सवाल उठाए थे। जिसमें कहा गया था कि अरावली जोन में तमाम फॉर्म हाउस, शिक्षण संस्थान, बाबाओं के आश्रम, मंदिर आदि वन विभाग की जमीन पर बने हुए हैं। जिन्होंने खोरी के लोगों के मुकाबले अरबों-खरबों की जमीन कब्जा कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए अलग से क्यों नहीं आदेश पारित किया। यही सवाल बंधुआ मुक्ति मोर्चा का भी है कि अमीर जब यहां बसाए जा सकते हैं तो गरीब क्यों नहीं बसाए जा सकते।

एक महत्वपूर्ण सवाल

फरीदाबाद के अरावली जोन में कहां वन क्षेत्र की जमीन है और कहां पुरानी आबादी का इलाका है, यह स्थिति साफ नहीं है। यानी वन विभाग खुद अपनी जमीनों की पैमाइश नहीं कर सका है। यह बहुत बड़ा चालाकी वाला खेल है। इसकी आड़ में कुछ फॉर्म हाउस बचा लिए जाएंगे और खोरी उजड़ जाएगा। खोरी में जब बसावट नहीं थी तो क्या वन विभाग ने कभी आकर लोगों को बताया कि उनकी जमीन की सीमा कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म होती है। पूरे अरावली जोन में यह घालमेल है। समझा जाता है कि जिस माफिया ने यहां पूर्वांचल के गरीब मजदूरों को जमीन बेची, उनमें पुलिस के अलावा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जरूर शामिल थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि खोरी पिछले 40 साल से भी ज्यादा वर्षों से बसा हुआ है, और वन विभाग ने अपनी जमीन की खबर ही न ली हो। कम से कम 40 साल पहले या 20 साल ही पहले खोरी में इतनी आबादी तो नहीं रही होगी, क्या वन विभाग सोता रहा। एमसीएफ ने यहां कानून टूटते देखे और उसके अफसर पैसा खाकर रिटायर हो गए। खोरी प्रशासनिक नाकामियों का जीता जागता उदाहरण है।

कहीं पेड़ काटे जाएंगे, कहीं लगाए जाएंगे

खोरी के उजड़ते ही यहां बड़े पैमाने पर पेड़ लगा दिए जाएंगे। वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक हाल ही में मुख्यमंत्री खट्टर ने जब वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि वन विभाग की जमीन जहां भी खाली कराई जाए, वहां फौरन पेड़ लगा दिए जाएं। इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दरअसल खोरी-लकड़पुर को उजाड़े जाने के मद्देनजर ही दिया था और अफसरों को इसे अच्छी तरह समझा भी दिया गया। विडम्बना देखिए कि एक तरफ मध्य प्रदेश के बकशवाहा जंगल के 2 लाख पेड़ों को काटकर हीरा निकाला जाएगा और दूसरी तरफ फरीदाबाद के खोरी गांव से लाखों लोगों को बेघर कर के पेड़ लगाएंगे। ये दोनों फैसले कोरोना से भी ज्यादा घातक होंगे। यह बात सरकार को देर-सवेर समझ में आ जाएगी।

अब तक तीन मौतें

खोरी में अभी अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू नहीं हुआ है लेकिन खोरी ने लोगों की जिन्दगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। अपने पीएफ के पैसे से यहां मकान बनाने वाले और अब मकान गिरने की आशंका से बेचैन होकर 72 साल के गणेशी ने यहां खुदकुशी कर ली। गणेशी की मौत बुधवार को हुई। इसी तरह दूसरा हादसा गुरुवार को हुआ, जब सामान ले जाते समय महिला की मौत हो गई। खोरी कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास रहने वाले पति-पत्नी इम्तियाज और आकांक्षा ने दिल्ली के संगम विहार में किराये का एक घर तलाश किया और गुरुवार को वहां शिफ्ट कर रहे थे। संगम विहार में किराये का कमरा तीसरी मंजिल पर है। टंकी उठाते समय आकांक्षा का पैर फिसला और वह नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। उसे बचाने की कोशिश में इम्तियाज भी गिर गया। उसकी हालत गंभीर है, उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य मौत की भी अपुष्ट सूचना है। लेकिन उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मजदूर मोर्चा अपने स्तर पर तीसरी मौत की पुष्टि नहीं करता है।

सहयोग के लिये सुधी पाठकों का धन्यवाद

'मज़दूर मोर्चा' की अपील का संज्ञान लेते हुए सुधी पाठकों ने जो आर्थिक सहयोग दिया एवं भविष्य में देते रहने का संकल्प किया है, उससे 'मज़दूर मोर्चा' आर्थिक संकट से काफ़ी हद तक उबर पाया है। दरअसल, बिक्री के दम पर चलने वाले इस साप्ताहिक पर कोरोना की मार काफ़ी भारी पड़ गयी। मार्च 2020 वाले लॉकडाउन तक जहां 4000 हजार प्रतियां बिकती थीं, डेढ़ माह बंद रहने के बाद 400 प्रतियों से शुरू करके 1700 तक पहुंच पाये थे कि फ़िर लॉकडाउन ने वापस 1000 पर ला पटका। लेकिन अब धीरे-धीरे वापस बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं इन दिनों न्यूज प्रिंट की कीमत भी 30 प्रतिशत बढ़ गयी।

लेकिन सुधी पाठकों ने जिस तरह से सहयोग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है वह काबिले तारीफ़ तो है ही अनापेक्षित भी लगा। फ़रीदाबाद से बाहर के तो अनेक ऐसे पाठकों ने सहयोग दिया जिनको हम निजी तौर पर जानते-पहचानते भी नहीं। स्थानीय ग़रीब मज़दूर पाठकों ने खुद मिल कर 50-50 रुपये का योगदान देते हुए जिस लहजे में कहा कि मेहनतकश वर्ग की इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, हमें भावुक कर दिया। इससे यह भरोसा पक्का हो गया है कि उद्योगपतियों व राजनेताओं की गोदी में बैठे बगैर, पाठकों के सहयोग से भी कोई अखबार चलाया जा सकता है।

सम्पादक मंडल

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

आईएएस अधिकारी के आदेश के बावजूद जालसाज दीपक के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर मोर्चा के 9-15 मई अंक में 'आखिरकार दीपक कपूर बर्खास्त, कई बड़े मामले में खुलेंगे फ़र्जी डिग्री के ज़रिए क्लर्क से साहब बन गया था शिक्षा विभाग में' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। जालसाज कपूर को नौकरी से बर्खास्त करने वाले आईएएस अधिकारी जे गणेशन सर्व शिक्षा अभियान निदेशक होने के साथ-साथ शिक्षा विभाग के भी निदेशक हैं। कपूर का बर्खास्तगी आदेश जारी करते समय उन्हें इस बात का पूरा आभास हो गया था कि वह विभाग में रहते हुए बड़े पैमाने पर धोखा-धड़ी का खेल खेलता रहा है। उसके तमाम घपले-घोटालों की तह में जाने के लिये उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करा कर तफ़्तीश कराना बहुत जरूरी है।

इसी उद्देश्य से जे गणेशन ने कपूर के बर्खास्तगी पत्र के साथ-साथ जिला प्रोजेक्ट कॉडिनेटर मनीष चौधरी को उसके विरुद्ध पुलिस में एफ़आईआर दर्ज कराने के लिये लिखा था। मई के पहले सप्ताह में आए उक्त आदेशों को कई दिन तक तो मनीष चौधरी छिपाकर बैठी रही लेकिन मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद इसे छिपाये रखना असम्भव हो गया तो कपूर को बर्खास्त किया गया।

रही बात एफ़आईआर दर्ज कराने की तो उसे भी मनीष चौधरी कई दिनों तक टालती रही। अंत में बड़े रुआंसे मन से मनीष चौधरी ने इस बाबत एक पत्र पुलिस आयुक्त कार्यालय में भेजवाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह पत्र अब सेक्टर 16 की पुलिस चौकी में आराम फ़रमा रहा है। हालात बता रहे हैं कि कपूर की ओर से हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि उसके विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज न की जाय।

दरअसल इस व्यवस्था में होता यह है कि दफ्तरों में चलने वाले हर कागज़ को आगे बढाने के लिये पैरवी करनी पड़ती है। मौजूदा मामले में मनीष चौधरी को केवल इतना ही करना था कि वह पुलिस आयुक्त को बताती कि उनके वरिष्ठ अधिकारी जे गणेशन का आदेश है कि यह मुकदमा दर्ज किया जाय। लेकिन इसके बरक्श मनीष चौधरी का पूरा प्रयास है कि यह मुकदमा दर्ज न हो पाये क्योंकि जानकारों के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद कपूर तफ्तीश के दौरान तोते के तरह जो कुछ बोलेगा उससे खुद मनीष चौधरी भी लपेटे जाने से बच नहीं पायेंगी। उनके द्वारा किये गये जिन घोटालों की फ़ाइल गुम हो गई बताते हैं वह दीपक कपूर के पास मौजूद है। यह खतरा अकेली मनीष चौधरी को ही नहीं अन्य उन कई कर्मचारियों के सिर पर भी मंडरा रहा है जिनको फ़र्जी डिग्रियां दिलाकर कपूर ने शिक्षा विभाग में भर्ती करा रखा है।

इन हालात में भ्रष्टाचार से लड़ रहे ईमानदार अधिकारी जे गणेशन को एफ़आईआर दर्ज कराने के लिये मनीष चौधरी के भरोसे न रहकर कोई दूसरा रास्ता अख्त्यार करना चाहिये।

विदित है कि मनीष चौधरी की सरकारी काम-काज में कतई कोई रूचि नही रहती। उन्हें दफ्तर आने तक कि फुर्सत नहीं होती, उच्च जिला अधिकारियों की मीटिंग में जाना उन्हें गंवारा नहीं होता। उनकी इस मौज-मस्ती के पीछे राजनीतिक संरक्षण बताया जाता है। जानकार बताते हैं कि पूर्व ज़िला भाजपा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री खट्टर के राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ का विशेष संरक्षण इन्हें प्राप्त है। गौड़ के इशारे पर ही कई अफ़सरों ने उन्हें मस्ती मारने की पूरी आज़ादी दे रखी है।

दरअसल गौड़ जैसे सलाहकारों ने सलाह तो क्या देनी होती है। इस बहाने अपनी अच्छी खासी दुकानदारी चलाकर माल-मलाई का जुगाड़ बना लेते हैं।

सुपरस्पेशिएलिटी अस्पताल के नाम पर कांग्रेसी विधायक नीरज की नौटंकी

फ़रीदाबाद (म.मो.) बिना कोई काम-धाम किये सुर्खियों में बने रहने के लिये एनआईटी से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा समय-समय पर कुछ न कुछ नौटंकी करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से मिल कर आग्रह किया कि सेक्टर 16 ए स्थित सनफ्लैग अस्पताल, जो अब हरियाणा सरकार के कब्जे में है, को ईएसआई के द्वारा बतौर सुपरस्पेशिएलिटी अस्पताल चलाया जाय।

विधायक को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि सुपरस्पेशिएलिटी अस्पताल आखिर चलाया कैसे जाता है, वह भी चारों ओर चल रहे बड़े व्यापारिक अस्पतालों के बीच। यदि उन्हें थोड़ी भी समझ होती तो वे ईएसआई मेडिकल कॉलेज की सुपरस्पेशिएलिटी सेवाओं को और अधिक बढाने व मजबूत करने की बात करते। उन्हें शायद इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि एनएच तीन स्थित इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर डिस्पेंसरियों व छोटे अस्पताल में हो सकने वाले कामों का भी पूरा बोझ लदा हुआ है। इस बोझ को कम करने के लिये डिस्पेंसरियों व छोटे अस्पतालों की कार्यकुशलता एवं दक्षता को बढ़ाया जाय। ईएसआई कवर्ड श्रमिकों का अधिकतम घनत्व फ़रीदाबाद तथा गुड़गांव क्षेत्र में ही है। इस पूरे क्षेत्र में न तो पर्याप्त डिस्पेंसरियां हैं और न ही छोटे अस्पताल। विधायक को अपने अल्प ज्ञान में वृद्धि करने के लिये जान लेना चाहिये कि ईएसआई मैनुअल के मुताबिक हरियाणा के 28 लाख बीमाकृत श्रमिकों के लिये 280 डिस्पेंसरियां होनी चाहिए और प्रत्येक डिस्पेंसरी में पांच डॉक्टर व 25 अन्य स्टाफ़। इसके बरक्स राज्य भर में कुल 79 डिस्पेंसरियां ही हैं। इसके लिये 280 डॉक्टरों के सवीकृत पद हैं जिनमें से 120 पद रिक्त पड़े हैं, यानी 280 की जगह भी मात्र 160 डॉक्टरों से मरीज़ों को बहलाने का प्रयास किया जा रहा है।

विधायक नीरज शर्मा ने सेक्टर आठ स्थित ईएसआई अस्पताल कभी न देखा हो तो कृपा करके उसे देख आयें। 200 बेड के अस्पताल की जो दुर्दशा आज है वही उस वक्त भी थी जब उनके पिता श्री इस विभाग के मंत्री होते थे। डिस्पेंसरियों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी जो आज है।

विधायक को यदि मज़दूरों की इतनी ही चिंता है और खट्टर साहब उनकी कोई बात सुनते व मानते हैं तो उनके द्वारा चलाये जा रहे ईएसआई हेल्थ केयर विभाग को चुस्त-दुरूस्त करें। ऊंचा सुनने वाले खट्टर के कानों में यह आवाज़ भी डाली जाय कि ईएसआई के तमाम अस्पतालों में डिस्पेंसरियों में रैबीज (कुत्ता काटे) इंजेक्शन बीते ढाई साल से नहीं आ रहे हैं, इसके लिये भी मरीज़ों को मेडिकल कॉलेज में आना पड़ता है, उन्य दवाईयों की तो बात ही क्या है।